

पंजीकृत

प्रेषक,

राज्य जन सूचना अधिकारी कम उप-निदेशक (पी एंड आई)
कार्यालय निदेशक, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

सेवा में,

श्री कुलदीप सिंह,
मकान नं0 1843, सैक्टर-26,
पंचकूला, हरियाणा।

यादि क्रमांक: 6/1(372)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/
दिनांक

विषय:- **Information under RTI Act, 2005.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की जाती है।
3. विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट अथोरिटी-कम-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।
4. यदि आप उपरोक्त अनुमान से असन्तुष्ट है तो आपको अपीलीय प्राधिकारी निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाता है।

संलग्न:

-Sd-
राज्य जन सूचना अधिकारी-सह-उपनिदेशक (पी एण्ड आई),
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: 6/1(372)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/

दिनांक

इसकी एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के पत्र क्रमांक 11/36/2016-4श्रम/एफ.
टी.एम.एस. 15432 दिनांक 08.08.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित की जाती है।

-Sd-
राज्य जन सूचना अधिकारी-सह- उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: 6/1(372)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/9499

दिनांक 31/8/16

इसकी एक प्रति प्रोग्रामर को कार्यालय की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाती है।

राज्य जन सूचना अधिकारी-सह- उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा।

96-B
22/8/16

SG

18/8/16

19-816

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे-श्री कुलदीप सिंह।

क्या राज्य जन सूचना अधिकारी कम उप निदेशक (पी एण्ड आई), उपरोक्त विषय पर सामान्य शाखा के पत्र क्रमांक 6/1(372)-RAI-G3-2016/8768 दिनांक 12.08.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

विषय सन्दर्भित मामले में श्री कुलदीप सिंह, मकान न0 1843, सैक्टर-26, पंचकुला द्वारा मांगी गई बिन्दु वाईज सूचना इस प्रकार है:-

बिन्दु	उत्तर
1. क्या आपके कार्यालय व आपके विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों की सभी लेखा शाखाओं में कर्मचारी द्वारा जमा/प्रेषित किये गए Essentiality Certificate व ईलाज के दौरान किये गए खर्च का ब्यौरा के कागजातों की छाया प्रतियां रिकार्ड में रखी जाती है। क) यदि हां तो उन कार्यालयों की लेखा शाखाओं की सूची प्रदान की जाए जो यह रिकार्ड रखती हैं। ख) यदि नहीं तो उन कार्यालयों की लेखा शाखाओं की सूची प्रदान की जाए जो यह रिकार्ड नहीं रखती हैं।	यह बिन्दु मुख्यालय की लेखा शाखा व अधीनस्थ कार्यालयों की लेखा शाखाओं से सम्बन्धित है।
2. यह आपके कार्यालय तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.2009 से सूचना भेजने की तिथि तक कितने Outdoor ईलाज के Medical Bill (खुला चिकित्सा भत्ता व Chronic Diseases के मामलों को छोड़कर) झा किये गये सूची प्रदान की जाए अर्थात ऐसे Outdoor ईलाज के Medical Bill झा करना जिसमें कर्मचारी फिक्सड मैडिकल भत्ता भी लेता हो और Outdoor ईलाज के Medical Bill भी पास करवाता हो, कि सूचना प्रदान की जाए।	मुख्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में (Chronic Diseases व खुला चिकित्सा भत्ता के मामलों को छोड़ कर) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के ओपीडी0 ईलाज के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को पास नहीं किया गया है।
3. सूचना प्रदान की जाए कि किन कारणों से ये आउट डोर ईलाज के मैडिकल बिल झा किये गये।	बिन्दु न0 2 अनुसार ही।
4. सूचना प्रदान की जाए कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी आउटडोर ईलाज के मैडिकल बिल (खुला चिकित्सा भत्ता व Chronic Diseases के मामलों को छोड़कर) झा करवा सकता है। यदि हां तो सरकार द्वारा जारी किये गये ऐसे रूल/सूचना/पोलिसी की सत्याप्रति प्रदान की जाए।	ऐसी कोई हिदायतें नहीं है।
5. सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आश्रितों के मैडिकल बिल झा करवाए जाते हैं। कृपया सूचना प्रदान की जाए कि आश्रित कौन है, परिभाषित करें।	हिदायतों की प्रति सलग्न है।
6. यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पिता केन्द्र सरकार व राज्य सरकार (दोनों से) से पेंशन भोगी है, तो क्या ऐसे कर्मचारी के पिता, कर्मचारी के आश्रित माने जाएंगे? यदि हां तो तथ्यों के आधार पर सूचना उपलब्ध करवाई जाए।	पेंशन भोगी माता/पिता आश्रित नहीं माने जाएंगे।

सेवा में,

राज्य जन सूचना अधिकारी कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)

अशा10 पत्र क्रमांक-1/70-ई0एस0आई0-एम0आर0-2016 / 1446

दिनांक 18/8/2016

चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय)

Annexure

By pass coronary surgery:

1. Southern Railway Headquarter Hospital, Perembur (Madras).
2. K.E.M. Hospital, Bombay.
3. Christian Medical College & Hospital, Vellore.
4. Jaslok Hospital, Bombay.
5. Bombay Hospital, Bombay.
6. Kasturba Hospital, Bombay.
7. Appopo Hospital, Madras.
8. Sree Chitra Tribunal Institute of Medical Sciences & Technology, Trivandrum.

Kidney Treatment:

1. Christian Medical College Hospital, Vellore.

Blood Cancer:

1. Tata Memorial Hospital, Bombay.
2. Cancer Institute Adayar, Madras.

Complicated heart surgery cases:

1. Southern Railway Hospital, Perembur, Madras.
2. Christian Medical College & Hospital, Vellore.
3. K.E.M. Hospital, Bombay.
4. Bombay Hospital, Bombay.
5. Sree Chitra Tribunal Institute of Medical Sciences & Technology, Trivandrum.
6. S.S.K. M. Hospital, Calcutta.
7. Kasturba Hospital, Bhopal (BHEL).
8. Semaritan Hosp. Always (Kerala).
9. N.M. Wadia Ins. of Cardiology, Pune.

Kidney Transplant:

1. Christian Medical College & Hospital, Vellore.

(viii) सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को पंचयुता में रहने वाली को पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में ईलाज करवाने हेतु स्थित सर्जन अम्बाला से रैफर न करवाने पर छूट वारे।

(न.स्वा.वि.हरि. 276/93-1 एवं पी. III वि. 17.3.93)

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को कठिनार्थों को सम्मुख रखते हुए केवल पंचयुता में स्थित सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में सीजे सी.एम.ओ. अम्बाला की एम्बुल के बिना ईलाज करवाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

2. यह हिदायतें वित्त विभाग की सहमति जो उनके अशा. क्रमांक 70/55/92-6 वि.विक.-II/3530, दिनांक 3.3.92 द्वारा प्राप्त कर ली गई है, से जारी किया गया है।

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

5. **Family/ Dependant/ Employed Spous**
(i) Reimbursement of medical charges to re-employed Govt. servants and their family members.

(Copy of P.b. Govt. H.D. letter No. 5160-JHBIV-63/25207, dt. 25.07.1963)

Under the existing provisions of the Punjab Services, (Medical Attendance) Rules, 1940 and other instructions issued on the subject from time to time, the concession of free medical attendance and treatment is not admissible to members of the families of re-employed Govt. employees. The question has been considered by Govt. and it is felt that since the re-employed Govt. employees are also temporary Govt. employees and members of their families should be allowed the same benefit of free treatment and attendance as is permissible to the family members of other temporary employees of the State Govt. under the Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940. Government further observe that the Govt. of India also allowed the concession of free treatment etc., to the family members of their re-employed employees. It has, therefore, been decided that the family members of the re-employed employees of the Punjab Govt. will also henceforth be entitled to free treatment and attendance under the Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940 subject to the conditions laid in the instructions issued by Govt. on the subject from time to time.

2. (For Director, Health Services Punjab Only). Necessary draft amendment to the Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940 may be forwarded to Govt. for their approval.

3. These instructions issue with the concurrence of the Finance Deptt. received with their U.O. communication No. 2739-FDI-63, dated 28th May, 1963.

- (ii) Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940
Dependent on Government employees & Wives and sons-
Definition of -

(Copy of H.D. Hr. No. 1062-USFP-Cell-69, dt. 25.2.69)

A few instances have come to the notice of the State Government where the State Government employees claimed re-imbusement of Medical expenses of their wives/sons who are also earning members. According to the Government instructions issued vide erstwhile Punjab Government letter no. 3601-4HBI-65/14112, dated

6.5.65 a wife/son can only be member of the 'Family' defined in the said letter, if she/he is residing with the Government servant concerned and is wholly dependent upon him (Government Servant); but in the case of a wife/son who is employed in a private institution or is earning her/his livelihood through some other sources, she/he cannot be covered under the term "wholly Dependent". As such Government servants are not entitled to claim reimbursement of Medical expenses in respect of their wives/sons who are earning members.

2. Keeping the above in view, the State Government have decided that in future no reimbursement of Medical expenses in such cases should be allowed to Government employees. However, the past cases need not be reopened.

3. I may also make it clear that if the wife of a State Government employee is an employee of the Haryana State, she is of Course allowed reimbursement of the medical expenses and her husband can also claim reimbursement of her medical expenses on her behalf in accordance with the existing Rules but this provision is not applicable to the sons of Government employees irrespective of the fact whether they (son/are employee) of the State Government or not. (2) **Dr. 25.3.69** to be traced

(iii) **Punjab Medical Attendance Rules, 1940-Definition of Family - Extension of benefit to parents and parents-in-law of female Government Servants.**

(Copy of H.D.Hr. No. 2235-USFP-Cell-69/11233, dt. 30.4.69)

I am directed to address you on the subject noted above and to say that a question has been raised whether the term "Wholly dependent parents" for the purpose of the term "Family" includes parents of a female employee. After a careful consideration it has been decided that a female Government servant will be given the choice to include either her parents, or her parents-in-law, for the purpose of availing of the benefits of the medical concession under the Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940, subject to the condition of dependance and residence as stipulated in office memorandum issued vide Haryana Government letter No.2087-68/6129, dated the 25.3.69.

2. This issues with the concurrence of the Finance Department received with their U.O. No. 1743-2FD-689, dated 16.4.69.

(iv) **Punjab Medical Attendance Rules - Dependent employees - wives.**

(Copy of H.D.Hr. No. 4197-USFP-Cell-7024708, dt. 11.9.70)

I am directed to invite attention to Haryana Government letter No. 1062-USFP-Cell-69, dated 26.2.69, on the subject noted above and to say that the State Government have on reconsideration decided that the husband and or wife of the State Government employees as the case may be, employed in a State Government or a private organisation which provide medical services would be entitled to choose either the facilities under the Punjab Services Medical Attendance Rules, 1940, or the medical facilities provided by the Organisation in which he or she is employed. In other words, in the instant case under reference if the wife chooses the facilities under Punjab Services Medical Attendance Rules, 1940, in preference to the medical facilities provided by her employer, her husband can claim re-imbursment of medical charges in respect of her treatment from the State Government under the Punjab Services Medical Attendance Rules, 1940.

2. I may also add that the condition of dependency or wholly dependent both in the case of husband or the wife of the State Government employees has been dispensed with under the Punjab Medical Attendance Rules, 1940, and the instructions issued vide Haryana Govt letter No. 1069-USFP-Cell. 69, dated 26.2.69 may be treated to have been modified to this extent. Thus the State Government employe can claim reimbursement of medical expenses irrespective of her source of income.

3. I am to add that certificate which is given by a State Government employee on the Essentiality Certificate for the dependency of his wife/ husband at the time of submitting re-imbursment bill should be amended accordingly.

This issues with concurrence of the Finance Department - vide their U.O. No. 1126-1FD-1170, dated 31.8.70.

(v) **Pb Services (MA) Rules 1940-Reimbursement of Medical Expenses Regarding & dependent Children.**

(Copy of H.D. Hr. No. 27290/1 HBH-81 dt. 8.1.82)

I am directed to refer to the subject noted above and to say that the matter regarding the admissibility of medical facilities to the family member of Govt. employees where both Spouses are State Govt. employees or are

employees of such organisation who extend medical facilities to their employees in the form of a fixed medical allowance have been engaging the attention of State Govt. for some time past. After careful consideration Govt. have now derided as Under:-

i) If both the husband & wife are state Govt. employees any one of them may be allowed to claim the reimbursement provided that they should furnish to their respective department a joint affidavit as to who will prefer the claim for reimbursement of medical expenses incurred on the treatment in respect of wife/husband and the children and a copy of each of this shall be kept in their Administrative Department and the claimant will submit a certificate every time to the effect that the amount being claimed has not been claimed by his/her spouse.

ii) If the husband/wife of a Govt. servant is employed in a Bank getting fixed Medical Allowance, he/she is not entitled to reimbursement of medical expenses in respect of wife/husband and their children. As the fixed medical allowance allowed by the Bank covers the whole of Family members. This should be brought to the notice of all concerned.

2. This decision will take effect from the date of issue of this letter.
3. These instructions will also apply to the officers/officials of Government managed Corporation.

(vi) **Pb. Service (Medical Attendance) Rules. 1940**
Reimbursement of medical expenses-Regarding, dependent children etc.

(Copy of H.D. Hr No. 2/20/83-IHBIII dt. 1.8.83)

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप को उपरोक्त विषय पर सम्बन्धित करूँ तथा कहूँ कि सरकार ने निर्णय लिया है कि दम्पति के केस में कोई भी स्थायज (वर्ल्ड/पति) अपने तथा अपने पर आश्रित बच्चों की चिकित्सा के खर्च की प्रतिपूर्ति किसी राज्य सरकार से जहाँ वह काम कर रहे हों कलेम कर सकता है। परन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी आप्रेशन देनी होगी कि उनमें से किस व्यक्ति द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति कलेम अपने राज्य में किया जायेगा। ऐसा करते समय उसे अपने कलेम की डुब्लिकेट प्रति तैयार करनी चाहिए तथा जो कलेम वह अपने राज्य से कर रहा है वृत्त स्थायज द्वारा उसकी प्रति अपने कार्यालय में भेजी जाय गी। उक्त उक्त राज्य सरकार को पता चल जाए कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कलेम

किस कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति यदि भविष्य में याहे आप्रेशन को तब्दील भी करवा सकते हैं कि किस राज्य सरकार से वे चिकित्सा प्रतिपूर्ति कलेम करना पसन्द करेंगे।

2. यह हिदायतें तुरन्त प्रभाव में लागू होंगी। जहाँ तक कि पिछले केसों का सम्बन्ध है सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा जिस राज्य को अपना कलेम प्रस्तुत किया है वह उसी से प्रतिपूर्ति करवा लें। परन्तु ऐसे केसों में किये जाने वाले प्रतिपूर्ति के कलेम की प्रति दूसरी राज्य सरकार को भी भेज दी जाए। अपना कलेम प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित कर्मचारी को यह सटीकिकेट देना होगा कि उस द्वारा राज्य से जो कलेम किया जा रहा है वह दूसरी राज्य सरकार से नहीं किया गया है।

यह हिदायतें सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनके स्थायज पर लागू होंगी।

(vii) **Copy of H.D. Hr No. 2/290/IHBIII-81 dt. 17.8.84.**

I am directed to invite a reference to Haryana Govt. circular No.2/290/IHBIII-81, dt. 8th June, 1982 on the subject noted above & to say that the matter regarding the admissibility of medical facilities to the Govt. employees where one of the spouses is an employee of a bank which allows medical facilities to its employees in the form of a fixed medical allowance, has been reviewed and it has now been decided as under:

"If the husband of a Govt. servant is employed in a Bank, the Govt. servant (she) can claim reimbursement of medical expenses incurred only on her own treatment and if the wife of a Govt. servant is employed in a Bank, the Govt. servant can claim the reimbursement of medical expenses incurred by him on his own treatment and on the treatment of wholly dependent children and parents only; but in such cases the spouse working in the Bank will furnish a certificate to the Department of Govt. servant to the effect that he/she is not claiming reimbursement of medical expenses of his/her spouse and children from the Bank."

2. These instructions will come into force from the date of issue of this letter.

(viii) **Punjab Medical Attendance Rules, Dependents on State Govt. Employees, Wives/Sisters.**

(Copy of H.D. Hr. No. 2/144/07-1HB III dated 14.12.2007)
I am directed to invite your kind attention towards Haryana Govt.

letter No. 1069-USFP-Cell-69 dated 26.2.1969 on the subject cited above and to say that the condition of dependency or wholly dependent in case of spouse was dispensed with and these instructions were modified vide Haryana Government letter No. 4197-USFP-Cell/70/24708, dated 11th September, 1970 to this extent that the State Government employees are entitled to claim reimbursement of medical expenses of spouse irrespective of his/her source of income. Subsequently some confusion arose in this matter on the issuance of letter-dated 29.8.85 (that ceiling of the income i.e. Rs. 750/-per month is also applicable for spouse) though the letter dated 11.9.1970 is still in operation and now, it is again clarified that letter dated 11.9.70 is still in operation and State Govt. employees are eligible to claim medical reimbursement of spouse irrespective of his/her source of income.

2. State Govt. has also decided to include fully dependent sisters residing with the Govt. Employees in the definition of family for the purpose of medical reimbursement.

3. It has also been decided to increase the ceiling of income of dependents from Rs. 750/- to Rs. 3500/- per month for the purpose of medical reimbursement.

4. The decision mentioned in Para No. 2 and 3 above will be affected with immediate effect.

5. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed vide their U.O. No. 2383.2958/5FD/1/2007, dated 22.11.07.

(ix) **Liberalization of Punjab Medical Attendance Rules, 1940.**

(Copy of H.D. Hr. No. 2354/07-1HB/1 dated 8.1.2008)
I am directed to invite your kind attention towards Punjab State Government letter No. 5217-4118 HB IV, dated 30.11.1960 in which term "Family" was defined for the purpose of reimbursement of medical charges. After considering in details, Government has decided to amend the term "Family" for the purpose of medical reimbursement under:-

"Government servants" wife and husband in case of female Government servants, who is wholly dependent on him/her, legitimate children, step children, legally adopted children and parents, widowed daughters, sisters wholly dependent on him/her"

2. The decision will be applicable with immediate effect.

3. This issues with the concurrence of Finance Department and vide their U.O. No. 2458, 2204-5-FD/1/2001, dated 24.12.2007.

6. Pensioners & their spouse

(i) **Grant of free medical facilities to Haryana Government pensioners and their wives/husbands.**

(Copy of H.D. Hr. No. 138-2HB/68/12620, dt. 27.5.68)

The question of grant of free medical facilities to Haryana Govt. pensioners at State Hospitals/Dispensaries has been engaging the attention of the State Govt. for some time past. The moment Govt. employees quit service on retirement, they cease to be entitled to such medical facilities as they were receiving immediately before retirement resulting in great hardship to them at the advanced stage when some need for Medical facilities is the greatest. In order to give them some relief in this regard, it has been decided that the Haryana Government pensioners and their Wives/husbands as the case may be, will be entitled to free medical treatment, indoor and outdoor, including X-Ray, laboratory and other such examinations, as the State Hospital/Dispensaries etc., according to the status enjoyed by them at the time of retirement. The free treatment will also include the free supply of such medicines as are available/supplied at the Hospital/Dispensaries, etc. However, the cost of medicines which are required to be purchased from the market for treatment, outdoor as well as indoor, will be made by the Govt. pensioners themselves and no reimbursement is to be made.

2. The retired Govt. employees who were entitled to free medical of Contributory Provident Fund will also be entitled to free medical facilities/referred to above. The benefit of free Medical facilities will be available to all the pensioners who retired from Punjab Govt. before the re-organisation of the State but are now drawing pensions in the State of Haryana. The Haryana Govt. pensioners Treasuries in Chandigarh will be entitled to those facilities in Chandigarh Hospitals/Dispensaries. The Haryana Govt. pensioners settled in a State other than Haryana will be entitled to free medical treatment in any of the Hospitals/Dispensaries in Haryana State as and when they happen to visit this State and need Medical Treatment during the course of their stay

3. This issues with the concurrence of Finance Dept.--- vide their U.O. No. 3089-IFD-68, dated the 17th May, 1968.